The actual expenditure for 1995-% vis-a-vis budget allocation for 1996-97 in respect of OIL are as under :—

		Rs. in crores
1995-96	Actual	36.49
1996-97	Approved allocation	64.01
	Revised estimates	65.11

(0 At present there is no such proposal under consideration of the Government of India.

Feasibility study by IOC for taking over Haldia Unit of HFC

*305. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of Executive Director, IOC in "The Economic Times" dated 30th August, 1996 regarding the feasibility study by IOC for taking over Haldia unit of HFC;

(b) whether the feasibility study has since been completed;

(c) if so, whether Ministry's permission has been sought, as reported in the press statement; and

(d) if not, the likely time by which the feasibility study would be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) A preliminary study was conducted by Indian Oil Corporation Limited with the main consideration of utilising the land available with Haldia Unit of HFC. However, the same was not found feasible.

Since IOC is not interested in taking over the Haldia Unit of HFC, the question of its seeking permission of Government docs not arise.

कम से कम चार मंजिल के दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवासों/फ्लैटों का निर्माण

*306. श्री गोविन्दराम मिरी:
श्री शिव चरण सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपलब्ध भूमि का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से चार मंजिल से कम मंजिल के आवासों का निर्माण न किए जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तीन मंजिलों से कम वाले आवासीय एककों पर तथा स्वयं वित्त-पोषित योजनाओं आदि में सर्वेण्ट क्वार्टरों एवं गैराजों पर एक अतिरिक्त मंजिल के निर्माण हेतुत अनुमति देने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि गैराज और सर्वेण्ट क्वार्टर स्वयं वित्त पोषित योजना के तहत मंजूर सुनियोजित समूह आवास स्कीम का हिस्सा होते हैं। अतिरिक्त मंजिल/ढ़ांचे के रूप में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति देने से, स्कीम की वास्तुक, संरचनात्मक व विन्यास अनुधारणा को नुकसान पहुंचेगा।

परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता का उपयोग न किया जाना

*307. श्री राम जेठमलानी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन की स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजनावधि के दौरान उत्पादन क्षमता के औसत वार्षिक उपयोग के संबंध में आकलन क्या है;

(ग) क्या वांछित औसत उत्पादन क्षमता का उपयोग

न हो पाने के कारण विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना-अवधि के दौरान वर्ष-वार उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण कितनी राशि की अतिरिक्त हानि होने का अनुमान है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) और एवंराजस्थान परमाणु बिजलीघर के यूनिट-I और II, जिन्हें क्रमशः फरवरी, 1994 और अगस्त, 1994 से बड़े अनुरक्षण कार्य हेतु लिया हुआ है, को छोड़कर देश के परमाणु बिजलीघरों का वार्षिक औसत क्षमता उपयोग VIIIवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान क्रमशः 60%, 40%, 47 और 60% था, तथा चालू वर्ष में नवम्बर, 1996 के अंत तक यह 60% था। वर्ष 1993-94 के दौरान क्षमता गुणक मुख्यतः इस कारण कम रहे क्योंकि टर्बाइन में आग लगने की घटना के बाद नरोरा यूनिट-I को पुनःस्थापन के लिए लम्बे समय तक बंद कर दिया गया था और इसके फलस्वरूप नरोरा-II, मद्रास यूनिट-I और II तथा ककरापार-I को टर्बाइनों तथा सहयोगी तंत्रों का निरीक्षण करने और उनमें संशोधन करने के लिए बंद कर दिया गया था। काम कर रहे रिएक्टरों के कार्य-निष्पादन में पिछले दो वर्षों से उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है। 1995-96 और 1996-97 (नवम्बर तक) के दौरान उपलब्धता गुणक क्रमशः 68% और 65% हासिल किए गए। उत्पादन करने वाले नए यूनिटों नामतः एन०ए०पी०एस०-I और II , आर०ए०पी०एस०-I और II ने 1995-96 में क्रमशः 75%, 81%, 73% और 85% तथा 1996-97 में (नवम्बर तक) 73%, 74%, 85% और 87% वार्षिक उपलब्धता गुणक हासिल किए।

(ग) और (घ) परमाणु बिजलीघरों से बिजली का विक्रय करने के लिए यूनिट ऊर्जा प्रभार 62.8% के गणकीय क्षमता गुणक के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और यह वास्तविक क्षमता उपयोग पर निर्भर नहीं करता है। जब यूनिट मानकीय क्षमता गुणक से अधिक पर कार्य करते हैं तब लाभ की गुंजाइश अधिक होगी और इसी तरह इसके विपरीत होगा।

आठवीं योजनावधि के दौरान न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन के प्रचालन परिणाम नीचे दिए अनुसार हैं:—

1992-93	निवल लाभः 72 करोड़ रुपए
1993-94	निवल हानिः 146 करोड़ रुपए
1994-95	निवल लाभः 134 करोड़ रुपए
1995-96	निवल लाभः 152 करोड़ रुपए
1996-97	निवल लाभः 186 करोड़ रुपए

*(अनंतिम, नवम्बर, 1996 के अंत तक)

अनंतिम आंकड़ों के आधार पर न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ने 1996-97 के दौरान नवम्बर, 1996 के अंत तक 186 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया है। इस प्रकार VIII वीं योजनावधि के दौरान न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ने अब तक कुल मिलाकर 130 करोड़ रुपए निवल लाभ अर्जित किया है।

Energy Shortage in Eastern Region

*308. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the present overall energy shortage in the Eastern Region as a whole and Bihar in particular, with details thereof; and

(b) the measures being taken by Government to improve the availability of power in the Eastern Region, particularly in Bihar?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON"-CONVENTIONAL ENGERY SOURCES (DR S. VENUGOPALACHARI): (a) The energy shortage in the Eastern Region and Bihar during October, 1996 was 7% and 23.8% respectively. During the same period the peaking shortage in the Eastern Region and Bihar was 20.4% and 41.2% respectively.

(b) The following important measures are taken to improve the availability of power in Eastern Region and Bihar:

(i) Renovation and Modernisation of Thermal Plants for impriving the plant load factor;

(ii) Capacity addition to meet peaking shortage;

(iii) demand management;

(iv) Energy conservation; and